सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)

जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 • G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075

दूरभाष/Phone : 91-11-25074100 / 25074200

भाराराप्रा/ नीति दिशानिर्देश / वित्त एवं लेखा/ 2026
नीति परिपत्र सं. 3.3.35 / 2026 दिनांक 08th मई, 2026

{(ई-ऑफिस फाइल सं. NHAI/F&A/GST/CLARIFICATION-REPLY-Part (1) (कम्प्युटर सं. 220364 पर लिया गया निर्णय)}

NHAI/ Policy Guidelines/ Finance & Accounts /2026
Policy Circular No. 3.3.35/ 2026 dated 08th May, 2026

{(Decision taken on E-Office File No. NHAI/ F&A/ GST/ CLARIFICATION - REPLY - Part (1) (Comp No. 220364)}

विषय: एचएएम परियोजनाओं के अंतर्गत सड़क निर्माण की गतिविधि पर नियम में परिवर्तन के प्रभाव के स्पष्टीकरण के संबंध में।

Sub: Clarification on impact of Change in Law on the activity of Construction of Road under HAM Projects -reg.

Ref:
(1) Circular No. 3.3.15 dated 04.10.2017
परिपत्र संख्या 3.3.15 दिनांक 04.10.2017
(2) Circular No. 3.3.17 dated 23.10.2017
परिपत्र संख्या 3.3.17 दिनांक 23.10.2017
(3) Circular No. NHAI/F&A/GST -2017-18/ SM dated 05.03.2018
परिपत्र संख्या भाराराप्रा /एफ एंड ए/जीएसटी -2017-18/ एसएम दिनांक 05.03.2018
(4) Circular No. 3.3.20/2019 dated 29.07.2019
परिपत्र संख्या 3.3.20/2019 दिनांक 29.07.2019
(5) Circular No. NHAI/F&A/GST-2021-22/SM-Vol. IV dated 20.09.2022
परिपत्र संख्या भाराराप्रा /एफ एंड ए/जीएसटी -2021-22/SM-खंड IV दिनांक 20.09.2022
(6) Policy Circular No. 3.3.27/2022 dated 23.12.2022
नीति परिपत्र संख्या 3.3.27/2022 दिनांक 23.12.2022
(7) Policy Circular No. 3.3.34/2025 dated 17.09.2025
नीति परिपत्र संख्या 3.3.34/2025 दिनांक 17.09.2025

पृष्ठभूमि / Background -

A) भारत में 01.07.2017 से वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 लागू हुआ। इस अधिनियम में केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है, जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी), कार्य अनुबंध कर (डब्ल्यूसीटी)/राज्य मूल्य वर्धित कर (वैट), अतिरिक्त सीमा शुल्क (सीवीडी) और विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी), प्रवेश कर और चुंगी आदि।
Goods and Services Tax Act, 2017 was implemented in India with effect from 01.07.2017. The Act has subsumed various Indirect Taxes of both the Central and State Governments, such as Central Excise Duty, Service Tax, Central Sales Tax (CST), Works Contract Tax (WCT)/State Value Added Tax (VAT), Additional Custom Duty (CVD) and Special Additional Duty (SAD) apart from Entry Tax and Octroi etc.

Contd.....2/-

B) इसके बाद, भाराराप्रा ने एचएएम अनुबंध भुगतानों पर जीएसटी अधिनियम, 2017 के कार्यान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी कीं। तदनुसार, जीएसटी के प्रभाव की गणना के लिए एक्सेल आधारित टेम्पलेट सार्वजनिक डोमेन, अर्थात भाराराप्रा वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं।

Subsequently, the NHAI had issued Standard Operating Procedures (SOP) for implementation of GST Act, 2017 on HAM Contract Payments. Accordingly, excel based templates for calculation of effect of GST incidence have been uploaded on public domain, i.e., NHAI website.

C) यह देखा गया है कि उपयुक्त परिपत्र और अन्य स्पष्टीकरण जारी करने के बावजूद, लेखा परीक्षकों की कुछ विशिष्ट बिंदुओं पर अलग-अलग व्याख्याएँ थीं, जैसे कि मूल्य वृद्धि का प्रबंधन, विशिष्ट व्ययों की लागत के लिए वित्तीय मॉडल का संदर्भ, मार्जिन/लाभ का प्रबंधन आदि।

It has been observed that despite issuing suitable Circulars and other clarifications, the Auditors were having different interpretations on specific points viz. treatment of Price escalation, reference to Financial Model for cost of specific expenses, treatment of margins/ profits, etc.

D) अतः, कानून में परिवर्तन के प्रभाव की गणना के संबंध में विभिन्न व्याख्याओं से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए सभी हितधारकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। वित्तीय मॉडल के आधार पर कानून में परिवर्तन के कारण जीएसटी पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की गई और जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम संभव समाधान पर सहमति बनी।

Therefore, a meeting was held with all Stakeholders to sort out various issues, which are being interpreted differently for calculation of Change in Law impact. The GST implication on account of Change of Law on the basis of Financial Model were discussed and a consensus was arrived at for best possible solution, given the complexities involved.

E) तदनुसार, हितधारकों के साथ परामर्श में लिए गए निर्णयों के आधार पर, एचएएम परियोजनाओं में जीएसटी के निहितार्थों के कारण उत्पन्न होने वाले नियम में परिवर्तन (सीआईएल) मुआवजे की गणना करते समय एकरूपता के लिए निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं।

Accordingly, based on the decisions arrived at in the Stakeholder consultations, the following clarifications are issued for uniform adoption while calculating Change in Law (CIL) compensation arising due to GST implications in HAM Projects.

F) ये स्पष्टीकरण, दिनांक 29.07.2019 के परिपत्र संख्या 3.3.20/2019 और दिनांक 23.12.2022 के नीति परिपत्र संख्या 3.3.27/2022 के प्रावधानों को, इस परिपत्र में निर्धारित सीमा तक, जहां तक वे एचएएम अनुबंधों के तहत कानून में परिवर्तन के प्रावधानों की प्रयोज्यता से संबंधित हैं, इस परिपत्र के जारी होने से पहले की गई या न की गई किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रतिस्थापित करेंगे।

These clarifications shall supersede the provisions of Circular No. 3.3.20/2019 dated 29.07.2019 and Policy Circular No. 3.3.27/2022 dated 23.12.2022, to the extent set out in this Circular insofar as they pertain to the applicability of Change in Law provisions under HAM contracts without prejudice to any actions taken or omitted to be taken prior to the issuance of this Circular.

Contd.....3/-

1) **अधिसूचना संख्या 03/2022 - केंद्रीय कर (दर) दिनांक 13.07.2022 के माध्यम से सड़क निर्माण सेवाओं पर जीएसटी दर में 6% से 9% तक परिवर्तन के बाद, सड़क निर्माण सेवाओं पर जीएसटी की कुल दर 12% से बढ़कर 18% हो गई है, जो 18.07.2022 से प्रभावी है, तदनुसार निम्नलिखित को आगे स्पष्ट किया जाता है:**
Pursuant to the change in GST rate on road construction services from 6% to 9% vide Notification No. 03/2022 - Central Tax (Rate) dated 13.07.2022 thereby increasing the overall rate of GST on Road construction services from 12% to 18% effective from 18.07.2022, Accordingly the following is hereby further clarified:

प्रारंभ में यह स्पष्ट किया जाता है कि दर में परिवर्तन की यह स्थिति केवल उन्हीं परियोजनाओं के लिए नियम परिवर्तन के अंतर्गत आएगी, जिनमें संविदा करार में नियम परिवर्तन की परिभाषा (सामान्यतः: अनुच्छेद-42) में विशेष रूप से किसी भी कर की दरों में परिवर्तन को शामिल किया गया हो, जिसका परियोजना पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता हो। इसके अतिरिक्त, 12% से 18% तक की दर में परिवर्तन की प्रयोज्यता सीजीएसटी अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत आपूर्ति के समय के प्रावधान के अनुसार शासित होगी।
At the outset, it is clarified that this event of change in rate shall be covered under Change in Law only for those Projects where the definition (Generally: ARTICLE-42) of Change in Law in the Contract Agreement specifically covers the event of any change in rates of any taxes that have a direct effect on the project. Further, the applicability of change of rate from 12% to 18% shall be governed in accordance with provision of time of supply under Section 14 of the CGST Act.

जीएसटी व्यवस्था की शुरुआत और उसके बाद वार्षिकी पर कर लगने के नियमों में हुए बदलावों के साथ-साथ कर दरों में संशोधन के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं:
In the context of the introduction of the GST regime and subsequent changes in the taxability of annuity as well as revisions in tax rates, the following scenarios may arise:

(i) **एचएएम परियोजनाएं जिनके लिए बोली की अंतिम तिथि 30.06.2017 या उससे पहले थी:**
HAM Projects where bid due date was on or before 30.06.2017:

जिन परियोजनाओं के लिए बोली की अंतिम तिथि 30.06.2017 या उससे पहले थी, उनके लिए निम्नलिखित दो स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं:
For the projects where the bid due date was on or before 30.06.2017, the following two situations may arise:

A. 17.07.2022 या उससे पहले कार्य पूर्ण होना (कर की दर में परिवर्तन से पहले), या
Work completed on or before 17.07.2022 (before change in rate of tax), or

B. 18.07.2022 या उसके बाद कार्य पूर्ण होना (कर की दर में परिवर्तन के बाद)।
Work completed on or after 18.07.2022 (after change in rate of tax).

Contd.....4/-

मौजूदा टेम्पलेट **अनुलग्नक-II (इस परिपत्र के साथ संलग्न)** दोनों स्थितियों के लिए लागू होगा।

The existing template **Annexure-II (attached to this circular)** shall be applicable for both the situations.

प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) संबंधी खर्चों के लिए, मौजूदा अनुबंध II के आधार पर परियोजना के लिए परिकलित सीआईएल क्षतिपूर्ति प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार लागू होगा:
For O&M-related expenses, the CIL compensation percentage computed for the project based on the existing Annexure II shall apply to O&M expenses as follows:

A. 17.07.2022 तक निष्पादित परियोजना के जीएसटी-पश्चात कार्य के लिए परिकलित सीआईएल प्रतिशत 17.07.2022 तक जारी किए गए सभी प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) इनवाइस पर लागू होगा।
The CIL percentage computed for the project's post-GST work executed up to 17.07.2022 shall apply to all O&M invoices raised up to 17.07.2022.

B. 17.07.2022 के बाद निष्पादित परियोजना के जीएसटी-पश्चात कार्य के लिए परिकलित सीआईएल प्रतिशत 17.07.2022 के बाद जारी किए गए सभी प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) इनवाइस पर लागू होगा।
The CIL percentage computed for the project's post-GST work executed after 17.07.2022 shall apply to all O&M invoices raised after 17.07.2022.

(ii) एचएएम परियोजनाएं जहां बोली की अंतिम तिथि 01.07.2017 और 13.10.2017 के बीच थी (दोनों दिन शामिल):
HAM Projects where bid due date was between 01. 07.2017 and 13.10.2017 (both days inclusive):

01.07.2017 से 13.10.2017 की अवधि के दौरान, जीएसटी सहित बोलियां आमंत्रित की गईं और निर्माण सहायता और वार्षिकी दोनों कर योग्य थे, इसलिए कंसेसनेयर से अपेक्षा की जाती है कि वह बोली तैयार करते समय परियोजना लागत में 12% जीएसटी को ध्यान में रखे।
During the period between 01.07.2017 to 13.10.2017, the bids were invited inclusive of GST and both construction support and annuities were taxable, hence, the concessionaire is expected to consider GST @ 12% in project cost while preparing the bids.

उपरोक्त स्थिति (ii) में, यदि इनवाइस (निर्माण सहायता या वार्षिकी दोनों के मामले में) 18.07.2022 को या उसके बाद जारी किया जाता है, तो कर की दर में 12% से 18% की वृद्धि के कारण कानून में परिवर्तन के तहत जीएसटी मुआवजे की गणना निम्नानुसार की जाएगी:
In the above situation (ii), if the invoice is raised (both in case of either construction support or annuity) on or after 18.07.2022, the GST compensation under Change in Law due to change in rate of tax from 12% to 18% shall be calculated as under:

Contd.....5/-

<u>व्याख्या 1/</u>
<u>Illustration 1.</u>

आइए 18.07.2022 को या उसके बाद होने वाले शेष भुगतान और वृद्धि पर विचार करें। Let us consider the balance payment plus escalation on or after 18.07.2022	Rs. 100
18.07.2022 से पहले लागू जीएसटी GST applicable before 18.07.2022	12%
जीएसटी को छोड़कर प्राप्त शेष राशि का मूल्य Derived balance works value excluding GST	Rs. 100/1.12 = Rs. 89.29
18.07.2022 से शेष भुगतान मूल्य पर जीएसटी को छोड़कर 18% की दर से जीएसटी लागू GST applicable from 18.07. 2022 @ 18% on balance payment value excluding GST	Rs. 89.29 X 1 8% = Rs. 16.07
जीएसटी सहित संशोधित राशि Revised Amount including GST	Rs. 89.29 + Rs. 16.07 = Rs. 105.36
निवल प्रभाव Net Impact	Rs. 5. 36 or 5. 36%

उपरोक्त प्रभाव उन प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) भुगतानों पर भी लागू होगा जिनके **इनवाइस** *18.07.2022 को या उसके बाद जारी किए गए हैं।*
The above impact will also be applicable on O&M payments where invoices are raised on or after 18.07.2022.

इस स्थिति (ii) के अंतर्गत, फील्ड इकाइयों को सूचित किया जाता है कि यदि कार्य पूर्ण होने की तिथि और कर **इनवाइस** *जारी करने की तिथि, जिसमें माइलस्टोन, वार्षिकी* **इनवाइस**, *ओएंडएम* **इनवाइस** *आदि शामिल हैं, 18.07.2022 से पहले की है और भुगतान 18.07.2022 को या उसके बाद किया गया है, तो करों की दर में परिवर्तन से संबंधित कानून में परिवर्तन के तहत कोई जीएसटी मुआवजा नहीं दिया जाएगा।*
Under this situation (ii), field units are advised that where the work completed and date of raising of tax invoice including milestone, annuity invoice, O&M invoice etc. is before 18.07.2022 and payment is made on or after 18.07.2022, no GST compensation under Change in Law regarding change in rate of taxes shall be paid.

यद्यपि, यदि अग्रिम के लिए वाउचर 18.07.2022 से पहले जारी किया गया है, और कार्य संपन्न किया गया है तथा भुगतान भी 18.07.2022 को या उसके बाद किया गया है, तो ऐसे मामले में ऊपर गणना किए गए प्रभाव से भुगतान किया जाएगा।
However, in case of voucher for advance is issued before 18.07.2022 and work is performed and payment is also made on or after 18.07.2022, in such a case the impact as calculated above shall be paid.

जीएसटी की दर में यह बदलाव उन कर इनवॉइस पर लागू होता है, जिनमें माइलस्टोन, वार्षिकी भुगतान, ओ एंड एम इनवॉइस आदि शामिल हैं।
This change in rate of GST is applicable on the tax invoices including milestone, annuity payment, O&M invoice etc.

Contd.....6/-

(iii) एचएएम परियोजनाएं जहां बोली की अंतिम तिथि 14.10.2017 और 16.06.2021 के बीच थी (दोनों दिन शामिल):

HAM Projects where bid due date was between 14.10.2017 and 16.06.2021 (both days inclusive):

14.10.2017 से 16.06.2021 के बीच की अवधि में बोलियाँ जीएसटी सहित आमंत्रित की गई थीं। यहाँ, निर्माण सहायता कर योग्य थी, और सीबीआईसी द्वारा 13.10.2017 को जारी अधिसूचना संख्या 32/2017- केंद्रीय कर (दर) के कारण वार्षिकी को छूट प्राप्त माना गया था; अतः, कंसेसनेयर से यह अपेक्षा की जाती है कि बोलियाँ तैयार करते समय वह निर्माण सहायता पर 12% की दर से जीएसटी पर विचार करे, जबकि वार्षिकी को जीएसटी से छूट प्राप्त माना गया था।

During the period between 14.10.2017 to 16.06.2021, the bids were invited inclusive of GST. Here, Construction support was taxable, and annuities were deemed to be exempt due to Notification No. 32/2017-Central Tax (Rate), dated 13.10.2017 issued by CBIC, hence, the concessionaire is expected to consider GST @ 12% on construction support while preparing the bids and annuities were deemed to be exempt from GST.

However, vide its Circular No. 150/06/2021-GST dated 17.06.2021, CBIC had clarified that annuity payments under HAM projects were taxable at applicable rate from time to time (applicable rate of GST was 12%) and accordingly compensation of concessionaire for such increase in cost under Change in Law on annuity portion shall be determined as per Annexure-IV attached to this circular.

इसके अलावा, सीबीआईसी ने 13.07.2022 को अधिसूचना संख्या 03/2022 (दर) जारी किया है, जो 18 जुलाई 2022 से लागू है। इसमें भारत सरकार ने सड़कों, पुलों आदि के निर्माण पर कर की दर 12% से बढ़ाकर 18% करने का फैसला किया है, जिससे कंसेसनेयर के लिए निर्माण की लागत और बढ़ गई है।

Furthermore, CBIC has further issued Notification No. 03/2022 (Rate) dated 13.07.2022, effective from 18th July 2022 wherein it is decided by the Government of India to increase the rate of tax on construction of roads, bridges etc. from 12% to 18%, which has further increased cost of construction to concessionaire.

अतः, उपर्युक्त परिस्थितियों में और कंसेसनेयर से विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त होने के पश्चात्, कठिनाई को कम करने के उद्देश्य से, निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया जाता है:

Therefore, in the above given circumstances and after receiving various representations from concessionaires, to mitigate hardship, the following is clarified:

(A) चूँकि बोलियाँ तैयार करते समय (14.10.2017 से 16.06.2021 की अवधि के दौरान, दोनों दिन शामिल) निर्माण लागत को जीएसटी (जीएसटी की लागू दर 12%) सहित माना गया था, इसलिए जहाँ इनवॉइस 17.07.2022 को या उससे पहले जारी किया गया है, वहाँ कोई अतिरिक्त लागत नहीं दी जाएगी।

Contd.....7/-

That since the construction cost was considered inclusive of GST (applicable rate of GST 12%) while preparing bids (during the period from 14.10.2017 to 16.06.2021, both days inclusive), therefore no additional cost shall be given where the invoice is raised on or before 17.07.2022.

(B) जहाँ निर्माण लागत के लिए 18.07.2022 को या उसके बाद इनवॉइस जारी किया जाता है और कंसेसनेयर को अधिसूचना संख्या 03/2022 दिनांक 13.07.2022 के कारण लागत में वृद्धि (जीएसटी की दर में 12% से 18% की वृद्धि) का सामना करना पड़ा है, तो यह स्पष्ट किया जाता है कि भारारापा, ऊपर्युक्त खंड (ii) के तहत निर्धारित सूत्र के अनुसार, जीएसटी के अंतर के लिए कंसेसनेयर को 5.36% की दर से मुआवज़ा देगा।
That where the invoice is raised on or after 18.07.2022 for construction cost and concessionaire suffered increase in cost (increase in the rate of GST from 12% to 18%) due to Notification No. 03/2022 dated 13.07.2022, it is clarified that NHAI will pay compensation to concessionaire for GST difference @5.36% as per formula prescribed under clause (ii) above.

(C) चूंकि बोलियां तैयार करते समय (14.10.2017 से 16.06.2021 की अवधि के दौरान, दोनों दिन सम्मिलित) वार्षिकी को जीएसटी से मुक्त माना गया था, और बाद में सीबीआईसी परिपत्र संख्या 150/06/2021 दिनांक 17.06.2021 के कारण, वार्षिकी को 01.07.2017 से पूर्वव्यापी रूप से (12% की दर से) कर योग्य बनाया गया था और आगे अधिसूचना संख्या 03/2022 दिनांक 13.07.2022 के माध्यम से वार्षिकी पर जीएसटी दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई थी, वार्षिकी भाग के नियम में परिवर्तन के तहत लागत में इस तरह की वृद्धि के लिए कंसेसनेयर का मुआवजा अनुलग्नक-IV के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

That since the annuity was considered exempt from GST while preparing bids (during the period from 14.10.2017 to 16.06.2021, both days inclusive), and later on due to CBIC circular No. 150/06/2021 dated 17.06.2021, annuity was made taxable retrospectively (at the rate of 12%) w.e.f. 01.07.2017 and further the GST rate on Annuity was increased from 12% to 18% vide Notification No. 03/2022 dated 13.07.2022, the compensation of the concessionaire for such increase in cost under Change in Law on annuity portion shall be determined in accordance with Annexure-IV.

आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुलग्नक-IV के तहत, एसपीवी की उन लागतों पर, जिन पर जीएसटी लागू होता है, इनपुट जीएसटी की गणना के लिए जीएसटी की दरें, वे दरें होंगी जो बोलियाँ तैयार करने के समय प्रचलित थीं। उदाहरण के लिए, ईपीसी संविदाकार की लागत पर इनपुट जीएसटी की गणना 12% की दर से की जाएगी, न कि 18% की दर से। यह प्रावधान सुविधा की दृष्टि से अनुलग्नक -IV में भी शामिल किया गया है।
This is further clarified that under the Annexure-IV, the rates of GST for calculation of input GST on costs of SPV which attracts GST shall be the rates prevailing at the time of preparation of bids. For example, Input GST on EPC Contractor Cost shall be calculated@ 12% and not 18%. That this provision is also inserted in the ***Annexure-IV*** *for the sake of convenience.*

Contd.....8/-

(iv) एचएएम परियोजनाएं, जिनमें बोली जमा करने की अंतिम तिथि 17.06.2021 को या उसके बाद थी:
HAM Projects where bid due date was on or after 17.06.2021:

17.06.2021 से बोलियाँ जीएसटी को छोड़कर आमंत्रित की गई थीं; अतः, जीएसटी लागू दरों पर देय है।
Since 17.06.2021, the bids were invited exclusive of GST and hence, GST is payable at the applicable rates.

इस स्थिति (iv) के तहत, फील्ड इकाइयों का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया जाता है कि जहाँ कर इनवॉइस की तारीख–जिसमें माइलस्टोन भुगतान, वार्षिकी भुगतान, वार्षिकी पर ब्याज, ओ एंड एम भुगतान आदि शामिल हैं–18.07.2022 से पहले की है और भुगतान 18.07.2022 को या उसके बाद किया जाता है, तो 12% की लागू दर से जीएसटी देय होगा।
Under this situation (iv), attention of field units is invited to the fact that where the date of tax invoice including milestone payments, annuity payments, interest on annuity, O&.M payments etc. is before 18.07.2022 and payment is made on or after 18.07.2022, GST at the applicable rate of 12% is payable.

जीएसटी की दर में 12% से 18% तक का यह बदलाव उन कर इनवॉइस पर लागू होता है, जिनमें माइलस्टोन भुगतान, वार्षिकी भुगतान, वार्षिकी पर ब्याज, ओ एंड एम भुगतान वगैरह शामिल हैं, और जो 18.07.2022 को या उसके बाद जारी किए गए हैं।
This change in rate of GST from 12% to 18% is applicable to the tax invoices including milestone payments, annuity payments, interest on annuity, O&M payments etc. raised on or after 18.07.2022.

उपर्युक्त सभी उदाहरण सिर्फ़ उदाहरण के लिए हैं। पीआईयू को सलाह दी जाएगी कि वे जीएसटी मुआवज़े की गणना वाली फ़ाइल, केवल पैरा 1 (i) और 1(iii) (C) के लिए आगे की जाँच और जीएसटी सलाहकार/लेखापरीक्षक द्वारा सत्यापन के लिए जीएसटी सेल, भाराराप्रा मुख्यालय को भेजें। यद्यपि, भुगतान, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के अनुमोदन से संबंधित पीआईयू द्वारा ही जारी किया जाएगा। 'नियम में बदलाव' के तहत जीएसटी के दावे कंसेसनेयर द्वारा पीआईयू को सूचना देते हुए, जीएसटी सेल, भाराराप्रा मुख्यालय में जमा किए जाएँगे।
All the above illustrations given above, are for the purposes of example only. The PIUs shall be advised to send the GST compensation calculation file to GST cell, NHAI HQ only for Para 1 (i) & 1(iii) (C) for further scrutiny and vetting by GST Consultant/ Auditor. However, payment shall be released by respective PIUs with approval of RO concerned. The GST claims under Change in Law shall be submitted by the concessionaire to GST Cell, NHAI HQ, under intimation to PIU.

2) एचएएम परियोजनाओं के ईपीसी भाग पर नियम में परिवर्तन के तहत जीएसटी का निपटान नीति परिपत्र संख्या 3.3.27/2022 दिनांक 23 दिसंबर, 2022 के पैरा 1 के अनुसार किया जाएगा। इस संबंध में अनुलग्नक-III संलग्न है।

Contd.....9/-

GST under Change in Law on EPC portion of HAM projects shall be dealt in accordance with the Para 1 of the Policy Circular No. 3.3.27/2022 dated 23rd December, 2022. The **Annexure-III** in this regard is enclosed.

3) संबंधित आरओ / पीडी, कंसेसनेयर द्वारा प्रस्तुत की गई गणनाओं को क्रॉस-चेक करेंगे और गणना की गई राशि जारी करेंगे। आरओ / पीडी, कंसेसनेयर से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर उपलब्ध कराने के लिए कह सकते हैं, जिसमें कंसेसनेयर द्वारा लिए गए इनपुट कर क्रेडिट की राशि दिखाई गई हो।
The concerned RO / PD will cross-check the calculations submitted by the Concessionaire and release the amount calculated. RO/ PD may ask the Concessionaire to provide electronic credit ledger by showing the amount of input tax credit availed by Concessionaire.

4) किसी परियोजना में काम के हर भाग के लिए प्रतिशत बैंड एक्सेल टेम्प)लेट्स का अनुलग्नक - II देखें (को हर परियोजना में काम के अंतिम लागत के भाग पर आईई के आकलन के आधार पर माना जाना चाहिए और संबंधित पीडी और आरओ से अनुमोदित किया जाना चाहिए। स्वतंत्र इंजीनियर कंसेसनेयर द्वारा ,प्रस्तुत की गई विस्तृत गणना में दी गई मात्रा और किए गए कार्य के विवरण को सत्यापित करेगा।
The Percentage band for each component of work in a project (Ref. Annex-II of the Excel Templates) should be considered based on the IE's assessment on final cost components of works in each project and approved by the concerned PD & RO. The Independent Engineer will certify the quantities and work done details provided in the detailed calculation submitted by the Concessionaire.

5) निर्माण कार्य पूरा होने के समय, पीसीओडी/सीओडी जारी किए जाने से पहले, कंसेसनेयर अपनी ओर से जीएसटी के लिए एक विस्तृत मिलान विवरण तैयार करेगा।
At the time of Completion of Construction, before issuance of PCOD/COD, Concessionaire shall make a comprehensive reconciliation statement for GST at their end.

6) एक्सेल शीट में दिए गए घटक का वितरण और कर का प्रतिशत केवल सांकेतिक/अनुमानित हैं। परियोजना से जुड़े खास घटक और कर की दरें एक्सेल शीट में इनपुट के तौर पर ठीक से दर्ज की जानी चाहिए।
The component distribution and percentage taxes as provided in the excel sheet are indicative/notional only. Project specific components and tax rates are to be recorded properly as input in the excel sheet.

7) परियोजना निदेशक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या जीएसटी लागू होने के कारण लागत में कोई कमी आई है, ऐसी स्थिति में उसकी वसूली रियायत करार और भाराराप्रा के मौजूदा परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार की जाए।
The Project Director must ensure, if there is any, reduction in cost on implementation of GST. In such cases recovery shall be effected in accordance with the provisions of Concession agreement and the extant circulars of NHAI.

Contd.....10/-

8) अनुलग्नक- IV के संबंध में नियम में परिवर्तन के तहत जीएसटी मुआवजे के दावे भाराराप्रा नीति परिपत्र संख्या 3.3 .33/2024 दिनांक 12 नवंबर, 2024 के अनुसार शासित होंगे।
GST compensation claims under Change in law related to Annexure-IV shall be governed as per the NHAI Policy circular No 3.3.33/2024 dated 12th November, 2024.

9) इसके बाद, नियम में परिवर्तन के तहत जीएसटी दावों को कंसेसनेयर द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित वित्तीय मॉडल के अनुसार संसाधित किया जाएगा।
Henceforth, GST claims under Change in Law shall be processed in accordance with the approved Financial Model submitted by the Concessionaire.

10) रियायत करार की शर्तों के अनुसार 'नियम में परिवर्तन' के तहत किया गया भुगतान, जीएसटी अधिनियम, 2017 के अनुसार मुनाफाखोरी-रोधी खंड के अधीन है।
The payment made under 'Change in Law', as per the terms of Concession Agreement, is subject to anti-profiteering clause as per the GST Act, 2017.

11) किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, आरओ/पीडी आगे के मार्गदर्शन/निर्देश के लिए भाराराप्रा मुख्यालय से संपर्क करेगा।
In case of any clarifications, RO/PD shall contact NHAI HQ for further guidance/direction.

12) यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.

संलग्नक :यथोपरी।
Encl.: As stated above.

08/05/26

(सीएस. संजय कुमार पटेल/ CS. Sanjay Kumar Patel)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक(समन्वय) (i/c) Chief General Manager (Coord.)

प्रति/ To:

भाराराप्रा मुख्यालय/आरओ/पीआईयू/सीएमयू/साइट कार्यालयों के सभी अधिकारी।
All Officers of NHAI HQ/ ROs/ PIUs/ CMUs/ Site Offices.

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. पुस्तकालय की साइट पर प्रकाशन के लिए पुस्तकालय को।
   Library for hosting the Circular on Library site.

2. परिचालन के लिए वेब एडमिन को।
   Web Admin for Circulation.

3. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।
   PPS to Secretary, MoRT&H for Kind Information.

National Highways Authority of India

Regular - Annexure-II

1	Project/ Contract details				
	Name of the Contractor/ Concessionaire		Contract Agreement Number		Name of the Project
	GST No.		Date		Bill No.
			State		Date:

2	Payment Details				
a	b	c	d		e
	Pre-GST Regime	GST Regime			
Total construction cost (Bid Project Cost) plus Price Variation	Value of services rendered - as per Bid Project Cost plus price variation - upto 30.06.2017	Value of services rendered - as per Bid Project Cost plus price variation - from 01.07.2017 till 17.07.2022	Balance Value of services rendered - as per Bid Project Cost plus price variation - on or after 18.07.2022		Remarks
999.00	100.00	749.00	150.00		

3	Project Constituents	Percentage	Gross Original Value of the Contract	Percentage	Pre-GST	Percentage	Post GST upto 17.07.2022	Percentage	Post-GST post 17.07.2022
a	Gross Value of Contract	-	999.00	-	100.00	-	749.00	-	150.00
b	Less : Labour and allied charges (refer Point no 6 in Notes)	25.00%	249.75		25.00		187.25		37.50
c	Taxable Value for VAT	(a-b)	749.25		75.00		561.75		112.50
d	Less: Output VAT (refer Point no 7 in Notes)	5.50%	39.06		3.91		29.29		5.86
e	Cost plus Margin		959.94		96.09		719.71		144.14
f	Less : Margin of SPV	10.00%	87.27		8.74	-	65.43	-	13.10
g	**Cost of the Project(a-b)**	-	872.67		87.35	-	654.29	-	131.03
	Components of the Projects								
	Cost incurred by EPC Contractor (incl margin)								
i	Bitumen	9.17%	80.00	9%	8.00	9%	60.00	9%	12.00
ii	Steel	6.96%	60.72	6%	5.00	7%	45.00	8%	10.72
iii	Cement	4.35%	37.95	5%	4.00	5%	30.00	3%	3.95
iv	Aggregates, Sand etc	10.07%	87.84	10%	9.00	10%	65.00	11%	13.84
v	Pipes	0.87%	7.59	1%	1.00	1%	6.00	0%	0.59
vi	Oth. Materials	0.87%	7.59	1%	1.00	1%	6.00	0%	0.59
vii	HSD	10.31%	90.00	11%	10.00	11%	70.00	8%	10.00
viii	Labour	23.03%	200.98	22%	19.35	22%	144.29	28%	37.34
iX	Plant & Machinery	18.33%	160.00	18%	16.00	18%	120.00	18%	24.00
	Cost incurred by SPV								
x	Cost on which VAT or ED/ST is leviable	9.17%	80.00	9%	8.00	9%	60.00	9%	12.00
xi	Cost on which no VAT or ED/ST is leviable	6.88%	60.00	7%	6.00	7%	48.00	5%	6.00
		100%	872.67	100%	87.35	100%	654.29	100%	131.03

4	GST Implications (For balance work)	Factoring 1: % Component	Value of Item in Cost	Excise Duty (In Rs)	Excise duty (In %)	Input VAT/ CST (In Rs)	Input VAT/CST (In %)	Cost incl. Taxes	Factoring 2: % Component	Value of Item in Cost	Excise Duty (In Rs)	Excise duty (In %)	Input VAT/ CST (In Rs)	Input VAT/CST (In %)	Cost incl. Taxes
	Cost of the Project(a-b)	-			-		-	654.29	-	-	-	-	-		131.03
	Cost incurred by EPC Contractor (incl margin)														
i	Bitumen	8.28%	51.60	7.22	14.00%	1.18	2.00%	60.00	8.25%	10.32	1.44	14.00%	0.24	2.00%	12.00
ii	Steel	6.11%	38.10	4.76	12.50%	2.14	5.00%	45.00	7.26%	9.08	1.13	12.50%	0.51	5.00%	10.72
iii	Cement	4.07%	25.40	3.17	12.50%	1.43	5.00%	30.00	2.67%	3.34	0.42	12.50%	0.19	5.00%	3.95
iv	Aggregates, Sand etc	10.43%	65.00	-	0.00%	-	0.00%	65.00	11.07%	13.84	-	0.00%	-	0.00%	13.84
v	Pipes	0.81%	5.08	0.63	12.50%	0.29	5.00%	6.00	0.40%	0.50	0.06	12.50%	0.03	5.00%	0.59
vi	Oth. Materials	0.81%	5.08	0.63	12.50%	0.29	5.00%	6.00	0.40%	0.50	0.06	12.50%	0.03	5.00%	0.59
vii	HSD	11.23%	70.00	-	0.00%	-	0.00%	70.00	7.99%	10.00	-	0.00%	-	0.00%	10.00
viii	Labour	23.15%	144.29	-	0.00%	-	0.00%	144.29	29.85%	37.34	-	0.00%	-	0.00%	37.34
iX	Plant & Machinery	19.25%	120.00	-	0.00%	-	0.00%	120.00	19.19%	24.00	-	0.00%	-	0.00%	24.00
	Cost incurred by SPV														
x	Cost on which VAT or ED/ST is leviable	8.15%	50.79	6.35	12.50%	2.86	5.00%	60.00	8.12%	10.16	1.27	12.50%	0.57	5.00%	12.00
xi	Cost on which no VAT or ED/ST is leviable	7.70%	48.00	-	0.00%	-	0.00%	48.00	4.80%	6.00	-	0.00%	-	0.00%	6.00
ix	Cost of the Project	100.00%	623.33	22.78		8.18		654.29	100.00%	125.08	4.39		1.56		131.03

5	**Billing Pattern**		12%	18%
a	Value of the work done by the Contractor		749.00	150.00
b	Less : factored in Taxes (3 b + net of ix)		52.07	10.26
c	Adjusted Value of Work done	5a - 5b	696.93	139.74
d	Add GST (on Adjusted value of work done)		83.63	25.15
e	Value of Work due to Change in Law	(5c + 5d)	780.57	164.90
f	Additional liability of GST due to Change in Law	(5a - 5e)	31.57	14.90
	Percentage Impact		4.21%	9.93%
	Overall Impact		46.46	
	Overall Percentage		5.17%	

Notes :

1 The cells in Green are for input

2 The correct rate of taxes for Excise,CST,VAT are to be entered.

3 The rates for VAT/Output VAT are as may be applicable for respective states

4 The issue of closing stocks are not considered due to complexities involved

5 The Components & Taxes are indicative/notional. It has to be project specific and may change

6 **Labour and allied charges Cell as per the details given below:-**

a) If it is in percentage (%) , enter the percentage (%) in Cell no. C15

b) If it is based on absolute value, Justify the Absolute value in a separate sheet and put the value in Cell No. D15 (Calculation sheet to be enclosed)

7 **Output VAT as per the details given below:-**

a) If it is in percentage (%) , enter the percentage(%) in Cell no. C17

b) If it is based on input used, calculate in a separate sheet, put the value in Cell No. D17 (Calculation sheet to be enclosed)

Authority Engineer

Contractor

Project Director
NHAI

National Highways Authority of India

Composite - Annexure-II

1	Project/ Contract details				
	Name of the Contractor/ Concessionaire		Contract Agreement Number		Name of the Project
	GST No.		Date		Bill No.
			State		Date:

2	Payment Details				
	a	b	c	d	e
		Pre-GST Regime	GST Regime		
	Total construction cost (Bid Project Cost)	Value of services rendered - as per Bid Project Cost plus price variation - upto 30.06.2017	Value of services rendered - as per Bid Project Cost plus price variation - from 01.07.2017 till 17.07.2022	Balance Value of services rendered - as per Bid Project Cost plus price variation - on or after 18.07.2022	Remarks
	999.00	100.00	749.00	150.00	

3	Project Constituents	Percentage	Gross Original Value of the Contract	Percentage	Pre-GST	Percentage	Post GST upto 17.07.2022	Percentage	Post-GST post 17.07.2022
a	Gross Value of Contract	-	999.00	-	100.00		749.00	-	150.00
b	Less:-Output Vat	5.25%	52.45		5.25		39.32		7.88
c	Cost plus Margin		946.55		94.75		709.68		142.13
d	Less : Margin of SPV	10%	86.05	-	8.61		64.52	-	12.92
e	Cost of the Project(a-b)	-	860.50	-	86.14		645.16	-	129.20
f	Components of the Projects								
	Cost incurred by EPC Contractor (incl margin)								
i	Bitumen	9.30%	80.00	9%	8.00	9%	60.00	9%	12.00
ii	Steel	7.06%	60.72	6%	5.00	7%	45.00	8%	10.72
iii	Cement	4.41%	37.95	5%	4.00	5%	30.00	3%	3.95
iv	Aggregates, Sand etc	10.21%	87.84	10%	9.00	10%	65.00	11%	13.84
v	Pipes	0.88%	7.59	1%	1.00	1%	6.00	0%	0.59
vi	Oth. Materials	0.88%	7.59	1%	1.00	1%	6.00	0%	0.59
vii	HSD	10.46%	90.00	12%	10.00	11%	70.00	8%	10.00
viii	Labour	21.94%	188.81	21%	18.14	21%	135.16	27%	35.51
ix	Plant & Machinery	18.59%	160.00	19%	16.00	19%	120.00	19%	24.00
	Cost incurred by SPV								
x	Cost on which VAT or ED/ST is leviable	9.30%	80.00	9%	8.00	9%	60.00	9%	12.00
xi	Cost on which no VAT or ED/ST is leviable	7%	60.00	7%	6.00	7%	48.00	5%	6.00
		100%	860.50	100%	86.14	100%	645.16	100%	129.20

4	GST Implications (For balance work)	Factoring 1: % Component	Value of Item in Cost	Excise duty %	VAT/CST	Output VAT	Cost incl. Taxes	Factoring 2: % Component	Value of Item in Cost	Excise duty %	VAT/CST	Output VAT	Cost incl. Taxes
	Cost of the Project(a-b)	-		-	-		645.16	-	-	-	-		129.20
	Cost incurred by EPC Contractor (incl margin)												
i	Bitumen	8%	51.60	14.00%	2.00%	0%	60.00	8%	10.32	14.00%	2.00%	0%	12.00
ii	Steel	6%	38.10	12.50%	5.00%	0%	45.00	7%	9.08	12.50%	5.00%	0%	10.72
iii	Cement	4%	25.40	12.50%	5.00%	0%	30.00	3%	3.34	12.50%	5.00%	0%	3.95
iv	Aggregates, Sand etc	11%	65.00	0.00%	0.00%	0%	65.00	11%	13.84	0.00%	0.00%	0%	13.84
v	Pipes	1%	5.08	12.50%	5.00%	0%	6.00	0%	0.50	12.50%	5.00%	0%	0.59
vi	Oth. Materials	1%	5.08	12.50%	5.00%	0%	6.00	0%	0.50	12.50%	5.00%	0%	0.59
vii	HSD	11%	70.00	0.00%	0.00%	0%	70.00	8%	10.00	0.00%	0.00%	0%	10.00
viii	Labour	22%	135.16	0.00%	0.00%	0%	135.16	29%	35.51	0.00%	0.00%	0%	35.51
ix	Plant & Machinery	20%	120.00	0.00%	0.00%	0%	120.00	19%	24.00	0.00%	0.00%	0%	24.00
	Cost incurred by SPV												
x	Cost on which VAT or ED/ST is leviable	8%	50.79	12.50%	5.00%	0%	60.00	8%	10.16	12.50%	5.00%	0%	12.00
xi	Cost on which no VAT or ED/ST is leviable	8%	48.00	0.00%	0.00%	0%	48.00	5%	6.00	0.00%	0.00%	0%	6.00
ix	Cost of the Project	100%	614.21				645.16	100%	123.25				129.20

5	Billing Pattern			
			12%	18%
a	Value of the work done by the Contract		645.16	129.20
b	Less : factored in Taxes (3 b + net of ix)		70.28	13.83
c	Adjusted Value of Work done	5a - 5b	574.88	115.38
d	Add GST (on Adjusted value of work done)		68.99	20.77
e	Value of Work due to Change in Law	(5c + 5d)	643.87	136.14
f	Additional liability of GST due to Change in Law	(5e-5a)	(1.29)	6.94
	Percentage Impact		-0.20%	5.37%
	Overall Impact		5.65	
	Overall Percentage		0.73%	

Notes :

1. The cells in Green are for input
2. The correct rate of taxes for Excise,CST,VAT are to be entered.
3. The rates for VAT/Output VAT are as may be applicable for respective states
4. The issue of closing stocks are not considered due to complexities involved
5. The Components & Taxes are indicative/notional. It has to be project specific and may change

Authority Engineer

Contractor

Project Directc
NHAI

National Highways Authority of India

Revised Annexure-III

Template for Calculation of Amount Payable under Change in Law on basis of EPC Cost

Particulars		Amt. Rs. in Crore
Bid Project Cost (a)^		1,500.00
EPC cost (assumed)		1,300.00
Upfront Construction Support (b)	40.00%	600.00
Annuity Mode (c)	60.00%	900.00
Assumed percentage on construction support prescribed by NHAI circular (d)^^	5.36%	
Assumed CIL percentage as computed for Annuity (e)	8.20%	
CIL payable on upfront construction support (b)*(d)= (f)		32.16
CIL payable on Annuity (c) * (e) = (g)		73.80
Total CIL to be paid (f)+(g) = (h)		105.96
Cost bifurcation for CIL payment till Provisional Completion Certificate/ Completion Certificate:		
EPC Cost incurred till PCC/CC (i)		1,300.00
Cost on which CIL has been paid - construction support (b)		600.00
Cost on which CIL has to be paid (part of Annuity cost) (h) - (b) = (j)		700.00

CIL payment till PCC/CC:		
a) CIL on construction cost (f)		32.16
b) CIL on annuity portion paid till PCC/CC (j) * (e) = (k)		57.40
Total CIL to be paid till PCC/ CC (f) + (k) = (l)		89.56
Balance CIL to be paid along with annuity over 15 years (h) - (l) = (m)		16.40

Remarks

^ The above template for calculating the amount payable under Change in Law shall, mutatis mutandis, apply to any price adjustments to the BPC, including but not limited to price escalation, scope changes, and similar variations

^^. The CIL percentage of 5.36% mentioned under (d) is provided for illustrative purposes only. The actual CIL amount shall be calculated in accordance with the applicable NHAI policy circulars governing costruction support payments made on or after 18.07.2022. Please note that this percentage is prescribed due to change in GST rate from 12% to 18%. In case of any future rate amendments/ updations prescribed by CBIC, same shall be notified by NHAI.

S. No.	Payment No.	Payment %	Amount	Amount to be paid under change in law	Cumulative Amount Payable
1	Milestone 1	8	120.00	6.43	6.43
2	Milestone 2	8	120.00	6.43	12.86
3	Milestone 3	8	120.00	6.43	19.30
4	Milestone 4	8	120.00	6.43	25.73
5	Milestone 5	8	120.00	6.43	32.16
	Total Construction Support along with CIL		600.00	32.16	
6	CIL to be paid on annuity portion till PCC/CC			57.40	89.56
	Total CIL to be Paid till PCC/CC			89.56	
Table: CIL to be Paid along with Annuity					
1	Annuity 1	2.10	18.90	0.34	89.90
2	Annuity 2	2.17	19.53	0.36	90.26
3	Annuity 3	2.24	20.16	0.37	90.63
4	Annuity 4	2.31	20.79	0.38	91.01
5	Annuity 5	2.38	21.42	0.39	91.40
6	Annuity 6	2.45	22.05	0.40	91.80
7	Annuity 7	2.52	22.68	0.41	92.21
8	Annuity 8	2.60	23.40	0.43	92.64
9	Annuity 9	2.68	24.12	0.44	93.08
10	Annuity 10	2.76	24.84	0.45	93.53
11	Annuity 11	2.84	25.56	0.47	94.00
12	Annuity 12	2.93	26.37	0.48	94.48
13	Annuity 13	3.02	27.18	0.50	94.97
14	Annuity 14	3.11	27.99	0.51	95.48
15	Annuity 15	3.20	28.80	0.52	96.01
16	Annuity 16	3.30	29.70	0.54	96.55
17	Annuity 17	3.40	30.60	0.56	97.11
18	Annuity 18	3.50	31.50	0.57	97.68
19	Annuity 19	3.61	32.49	0.59	98.27
20	Annuity 20	3.72	33.48	0.61	98.88
21	Annuity 21	3.83	34.47	0.63	99.51
22	Annuity 22	3.94	35.46	0.65	100.16
23	Annuity 23	4.06	36.54	0.67	100.82
24	Annuity 24	4.18	37.62	0.69	101.51
25	Annuity 25	4.25	38.25	0.70	102.20
26	Annuity 26	4.25	38.25	0.70	102.90
27	Annuity 27	4.44	39.96	0.73	103.63
28	Annuity 28	4.71	42.39	0.77	104.40
29	Annuity 29	4.75	42.75	0.78	105.18
30	Annuity 30	4.75	42.75	0.78	105.96
	Total Annuity Payments plus price variation		900.00	16.40	
	Total		1,500.00	105.96	

National Highways Authority of India

Annexure-IV

Template for calculation of impact under Change in Law for the period with bid due date between 14.10.2017 to 16.06.2021 (both days inclusive)

Format for computation of Change in Law amount on annuity portion of Bid Project Cost as per the approved Financial Model submitted by the concessionaire

S.No.	Particulars		Amount
A.	Bid Project cost (as per financial model)		1,500.00
B.	Construction Support not liable under Change in Law	40% of A	600.00
C.	Annuity Payments liable for payment of GST under Change in Law	A-B	900.00
D.	Output GST on annuity payments	12%	0.00
		18%	162.00
	Total output GST on annuity payments		**162.00**
E.	Cost of SPV which attract GST (as per approved financial model)		
I	EPC Contractor Cost		1300.00
ii	Breakup of other costs leviable under GST		50.00
iii	(add more rows, if required)		0.00
F	**Total (sum of E i.e. i, ii, iii....)**		**1350.00**
G.	Cost of SPV which do not attract GST (as per approved financial model)		
i	Interest during construction		100.00
ii	Notional Profit / Margin (as per Financial Model)		40.00
Iii	Breakup of other cost not leviable under GST		10.00
Iv	(add more rows, if required)		0.00
H	**Total (sum of G i.e. i, ii, iii, iv....)**		**150.00**

Draft circular for change in law - HAM

	Total Bid Project Cost		1,500.00
I	Input tax credit of GST on F above (as per approved financial model)		147.00
J	Input tax credit of GST related to 40% of Construction Support	40% of I	58.75
K	Remaining input tax credit of GST related to Annuity Payments	I-J	88.25
L	Differential GST payable	D-K	73.75
M	GST impact %	L/C	8.20%

Notes:

1. It is to be noted that Bid Project Cost as per Annexure-IV should reconcile with the Bid Project Cost as per Financial Model.
2. The **GST compensation impact%** computed above would be applied towards the annuity payments made to concessionaire in relation to **BPC and related adjustment viz. price escalation, de-scoping, etc.**
3. Notional profit being considered while computing Change in Law should be in line with the acceptable range of margin disclosed in the financial model.
4. Financial Model has been defined in Model Concessionaire Agreement - extracts of which is captured below:

   *"**Financial Model**" means the financial model adopted by Senior Lenders, setting forth the capital and operating costs of the Project and revenues therefrom on the basis of which financial viability of the Project has been determined by the Senior Lenders, and includes a description of the assumptions and parameters used for making calculations and projections therein"*
5. Financial Model as defined in Model Concessionaire Agreement shall only be considered while computing the impact of Change in Law i.e. Financial Model submitted at the time of financial close.